रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट

4401. **डा. अबरार अहमद** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सवाई माधोपुर में रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के अधिकांश टाइगर और अन्य जानवर इस परियोजना के अधिकारियों की मिलीभगत से मारे जा चुके हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अधिकाश जंगल को इस परियोजना के अधिकारियों की मिलीभगत से कटवाया जा रहा है; यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करने के लिए वहां कोई दल अविलम्ब भेजेगी; और

(ग) क्या वन अधिकारियों और कर्मचारियों के, जो भ्रष्ट आचरण करते हैं और रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट को बर्बाद कर रहे हैं, विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। यह कहना सही नहीं है कि रणथम्भौर बाघ परियोजना के अधिकारियों की सांठ-गांठ से परियोजना के अधिकांश बाघ और अन्य पशु मारे गए हैं।

(ख) परियोजना के अधिकारियों की मिलीभगत से वृक्षों को काटे जाने के बारे में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्र सरकार ने रणथम्भौर बाघ रिजर्व में चोरी-छिपे शिकार और वृक्षों की अवैध कटाई की समस्याओं की जांच करने के लिए एक कृत्यक बल का गठन किया है।

(ग) रणथम्भौर बाघ परियोजना में कार्यरत वन अधिकारी और कर्मचारी राजस्थान राज्य सरकार के अनुशासनिक नियंत्रण में आते हैं। दोषी कर्मचारियों से निपटने के लिए निर्धारित निगम और विनियम विद्यमान हैं।

India's Plea at Unced

4402. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether India pleaded for a contribution of only 0.7 per cent of their GNP by the rich nations of the north, towards global environmental protection, without strains on the poor developing countries, while participating in the UNCED; and

(b) if so, what was the response and consensus of the Conference on this proposal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) At the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) held at Rio-de-Janeiro, in June 1992, the developing countries including India, demanded that new and additional financial sources be provided by the developed countries to implement Agenda 21, which is a plan of action for sustainable development in the future. The developed countries re-affirmed their commitment to reach the accepted United Nations target of 0.7 per cent of Gross National Product (GNP) for Official Development Assistance (ODA) to developing countries and to the extent that they have not achieved the target, agreed to augment their aid programmes in order to reach the target as soon as possible. This commitment forms part of the consensus reached on Agenda 21 adopted at the Rio Conference.

Committee for Implementation of Convention of Earth Summit

4403. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether with a view to overseeing the implementation of the conventions